लखनऊ, भोपाल, जयपुर, आगरा, गोण्डा, सुल्तानपुर, अमेठी और फैज़ाबाद में प्रसारित

हिन्दी व अंग्रेज़ी साप्ताहिक समाचारपत्र

खुशी समय

KHUSHI SAMAY

RNI No.: UPBIL/2012/46720

HINDI & ENGLISH WEEKLY NEWSPAPER

LUCKNOW

● वर्ष 9 ● अंक 37 | लखनऊ, रविवार 11 जुलाई 2021 | पृष्ठ - 8 मूल्य -2 रुपये

२ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कई और सुविधाओं से भी धोना होगा हाथ

लखनऊ (सरदार नक़ी लाल) उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में २ बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-२०२१ का प्रारूप तैयार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (न्चैस्) की वेबसाइट के मुताबिक, 'राज्य विधि आयोग, यूपी राज्य की जनसंख्या के नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण पर काम कर रहा है और एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है।' विधि आयोग ने इस विधेयक का प्रारूप अपनी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और १६ जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है। इस विधेयक के प्रारूप के अनुसार इसमें २ से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इसमें सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है।

प्रारूप में कहा गया है, 'दो बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले लोक सेवकों (सरकारी नौकरी करने वालों) को पूरी सेवा में मातृत्व या पितृत्व के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरे वेतन और भत्तों के साथ १२ महीने की छुट्टी और नियोक्ता के योगदान कोष में ३ प्रतिशत की वृद्धि की बात भी कही गयी हैं।' अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक राज्य जनसंख्या कोष का गठन किया जाएगा।

सरकार के कर्तव्यों को सूचीबद्ध करते हुए, मसौदा विधेयक में कहा गया है, 'सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र और गैर सरकारी संगठन गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम आदि वितरित करेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे और राज्य भर में गर्भधारण, प्रसव, जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।इसमें यह भी कहा गया है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक अनिवार्य विषय पेश करना सरकार का कर्तव्य होगा।

मसौदा विधेयक में कहा गया है कि दो बच्चों के मानदंड को लागू करने और बढ़ावा देकर राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण करने के उपायों को प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। इसमें कहा गया है, 'उत्तर प्रदेश में, सीमित पारिस्थितिक और आर्थिक संसाधन हैं। यह जरूरी है कि किफायती भोजन, सुरक्षित पेयजल, अच्छे आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सहित मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान हो। आर्थिकध आजीविका के अवसर, घरेलू उपभोग के लिए बिजली और एक सुरक्षित जीवन सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो।'

मसौदा विधेयक में कहा गया है कि अधिकाधिक एक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना, स्थिर करना आवश्यक है। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और इसके कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने से संबंधित उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दिलीप कुमार का जाना हमारे सांस्कृतिक जगत की हानि - पीएम मोदी

नई दिल्ली। दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिलीप कुमार के निधन को देश के सांस्कृतिक जगत की हानि बताये हुए कहा है कि उन्हें सिनेमा के लीजेंड के तौर पर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिलीप कुमार को उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शक मंत्रमुग्ध होते थे।

प्रधानमंत्री से पहले दिलीप कुमार के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शोक जताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार के असाधारण योगदान को आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। राहुल गांधी ने दिलीप कुमार के परिवार, मित्र और समर्थकों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है।

मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कुछ बीजेपी नेताओं को मिल सकती है यह जिम्मेदारी

नयी दिल्ली (आईएनआईएस) कुछ केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे से उनके समर्थक सकते में हैं। उन्हें इसका अंदेशा भी नहद्द था कि उनके नेता का मंत्री पद चला जाएगा। अब उनकी नई भूमिका को लेकर भी कयास लगने लगे हैं। संभावना है कि रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित १२ मंत्रियों की विदाई के बाद अब इनमें से कुछ को भारतीय जनता पाटी (बीजेपी) संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बुधवार को हुए फेरबदल और विस्तार में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पाटी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे पांच नेताओं को मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार के अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया है। वहद्ध, अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्यमंत्री बनाया गया है। इन दोनों नेताओं के अलावा पाटी के राष्ट्रीय सचिव विश्वेश्वर टुडु, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष एल मुरुगन को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। बीजेपी में 'एक व्यक्ति, एक पद' का सिद्धांत लागू है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार में शामिल किए गए नेताओं की जगह संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह संभावना जताई जा रही है कि प्रसाद, हर्षवर्धन और जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में भूमिका दी जा सकती है। इन तीनों नेताओं के अलावा थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रतापचंद सारंगी को भी मंत्रिपरिषद से हटाया गया है। गहलोत को तो कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे से राज्यसभा में नेता सदन का पद भी खाली हो गया है। वह पाटी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में लंबे समय तक दलित प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं।

पाटी संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त १० सदस्य होते हैं। पाटी महासचिवों में से एक इस संसदीय बोर्ड का सचिव होता है। लेकिन वर्तमान संसदीय बोर्ड में सात ही सदस्य हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बी एल संतोष शामिल हैं। संसदीय बोर्ड में भी तीन पद फिलहाल रिक्त हैं। वर्तमान में बीजेपी संगठन में भूपेंद्र यादव सहित आठ महासचिव, अन्नपूर्णा देवी सहित १२ उपाध्यक्ष और टुडु सहित १३ सचिव हैं। जनवरी २०२० में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा ने लगभग आठ महीने के बाद अपनी टीम बनाई थी। अभी तक पाटी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने के बाद अब कयास लगाए जाने लगे है कि पाटी संगठन में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।

हालांकि इस बारे में पाटी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि संगठन के बारे में नियुक्ति संबंधी कोई भी फैसला लेने का अधिकार अध्यक्ष का है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए प्रसाद, जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी बीजेपी संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जबकि हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। बहरहाल, जिन ३६ नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सात चेहरों को जगह दी गई। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को मिला है। इन राज्यों से चार-चार सांसदों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। गुजरात से तीन, मध्य प्रदेश, बिहार और ओड़िशा से दो-दो नेताओं को मंत्री बनाया गया है जबकि उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, नयी दिल्ली, असम, राजस्थान, मणिपुर ओर तमिलनाडु से एक-एक नेता को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है।

Ramagya Distributors Pvt. Ltd.
(Deals in Writing and Printing Papers)
Gwynne Road ,Aminabad ,Lucknow
Phone:0522-4001081,9415018235
We Deal In : *All Writing and Printing Paper Solutions
*Call For Printing and Writing Paper Solutions.

KHUSHI FOUNDATION
Smile for Every Face
C-695,Ist Floor,Sector-6,Indira Nagar,Lucknow-226016,
www.khushifoundation.net

केरल में मंगलवार को कोरना वायरस से संक्रमण के १४,३७३ नए मामले सामने आए।

तिरुवनंतपुरमरू केरल में मंगलवार को कोरना वायरस से संक्रमण के १४,३७३ नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सूबे में इस घातक वायरस के संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर २६,६६,०६४ हो गई। वहद्व, राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान में १८-२३ साल के कॉलेज के छात्रों, निजी बस कर्मचारियों और प्रवासी कामगारों को तरजीह देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने ऐसे लोगों को पर्यटन स्थल पर जाने की इजाजत देने की बात कही है जिन्होंने कोविड का टीका लगवा लिया है और जिनके पास आरटी-पीसीआर निगेटिव सर्टिफिकेट है।

सरकार ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि १०,७५१ व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर २८,७७,५५७ हो गई है। आंकड़े के मुताबिक, इस समय केरल में कुल १,०४,१०५ मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के कारण हाल ही में हुई १४२ मौतों के साथ सूबे में इस घातक वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर १३,९६० हो गई। विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य में अब तक, २,३७,६८,११२ सैंपल्स की जांच की गई है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में संक्रमण दर के अनुसार क्षेत्रों को पुनर्वगीऔत करने के बाद कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि जो आगंतुक टीका लगवा चुके हैं और जिनके पास त्ज्-च्ब्त् निगेटिव प्रमाण पत्र हैं, उन्हें पर्यटन स्थलों पर जाने की अनुमति दी जा सकती है। वहद्व, अगर कोरोना के मामलों में कमी आती है तो ही सरकार अन्य ढील देने के बारे में सोचेगी। सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए १८-२३ वर्ष की आयु के कॉलेज छात्रों, अतिथि श्रमिकों (प्रवासी श्रमिकों) और निजी बस कर्मचारियों को वरीयता देने का भी निर्णय लिया।

गुड न्यूज! गाजियाबाद के पास नोएडा जितने इलाके को बनाया जाएगा निवेश क्षेत्र, १० महीने के अंदर होगा ये बड़ा काम

नोएडा (आईएनआईएस) उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर यूपी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार निवेशकों से संवाद भी कर रही है और नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने पर भी विचार कर रही है, अब उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद और नोएडा के बेहद नजदीक दादरी और बुलंदशहर में लगभग नोएडा के बराबर के इलाके में निवेश क्षेत्र बनाने जा रही है। इसका नाम दादरी-गाजियाबाद- नोएडा निवेश क्षेत्र (डीजीएनआईआर) है।

ये निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दो जिलों गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के ८० गांवों में फैला होगा, जो करीब २०० वर्ग किलोमीटर के इलाके में होगा। नोएडा प्राधिकरण की ब्म्ट रितु माहेश्वरी ने एक आधिकारिक के जरिए बताया कि ष्इनमें से ६० गांव बुलंदशहर में आते हैं जबकि २० गांव गौतम बुद्ध नगर में हैं। खुर्जा और दादरी के बीच स्थित यह निवेश क्षेत्र २०० वर्ग किलोमीटर के इलाके में है जो लगभग नोएडा के बराबर है। दादरी-गाजियाबाद-नोएडा निवेश क्षेत्र (डीजीएनआईआर) के लिए मास्टर प्लान विकसित करने से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण और दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। श्मास्टर प्लान २०४१श् १० महीने के भीतर सौंप दिए जाने की उम्मीद है।

४२ प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की, एडीआर रिपोर्ट में किया गया दावा

नयी दिल्ली। (आईएनआईएस) चुनाव सुधारों के लिये काम करने वाले समूह एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री परिषद के ७८ मंत्रियों में से ४२ प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है जिनमें से चार पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। बुधवार को १५ नए कैबिनेट मंत्रियों तथा २८ राज्य मंत्रियों ने शपथ ली जिसके बाद मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या ७८ हो गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किये गए विश्लेषण में ३३ प्रतिशत (४२) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है। करीब २४ या ३१ प्रतिशत मंत्रियों ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। गृह राज्य मंत्री बने कूच बेहार निर्वाचन क्षेत्र के निशित प्रमाणिक ने अपने खिलाफ हत्या से जुड़े एक मामले की घोषणा की है। वह ३५ वर्ष के मंत्री परिषद के सबसे युवा चेहरे भी हैं। चार मंत्रियों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों की घोषणा की है। ये मंत्री हैं जॉन बारला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरलीधरन।

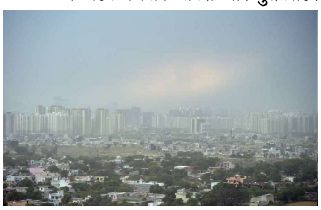

जिन मंत्रियों का विश्लेषण किया गया उनमें से ७० (९० प्रतिशत) करोड़पति हैं और प्रति मंत्री औसत संपत्ति १६.२४ करोड़ रुपये है। चार मंत्रियों ने ५० करोड़ रू से ज्यादा की संपत्ति का उल्लेख किया है। ये मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, नारायण तातु राणे और राजीव चंद्रशेखर।

बच्चों को महफूज बनाने में जुटी आधी आबादी

अनिल द्विवेदी खुशी समय

लखनऊ - कोविड-19 की तीसरी लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ने की आ रहद्व खबरों के बीच सरकार जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को चाकचौबंद करने में जुटी है वहीं माताएं अपने नौनिहालों को शारीरिक व मानसिक रूप से कोरोना से लड़ने के काबिल बनाने पर ध्यान दे रहद्व हैं । बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के बारे में डाक्टर से मिली सलाह का शत प्रतिशत पालन हो रहा है तो कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने की आदत डालने पर भी फोकस है। घर से बाहर न निकल पाने के कारण बच्चे मानसिक रूप से परेशान न हों इसके लिए परिवार के लोग इनडोर गेम या अन्य गतिविधियों में उन्हें व्यस्त रखने की कोशिश में जुटे हैं ।

खानपान का रख रहीं ख्याल : इंदिरानगर निवासी ऋचा द्विवेदी अपनी साढ़े तीन साल की बेटी को किसी भी संक्रमण से मजबूती से लड़ने के काबिल बनाने में जुटी हैं । उनका कहना है कि बच्चे की इम्यूनिटी जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूती से वह बीमारियों से लड़ सकेगा । खाने में हरी साग सब्जियों और मौसमी फल पर जोर दे रही हैं तो शरीर में पानी की कमी न होने पाए उसका भी ख्याल रख रही हैं । बेटी को फलों का जूस देने के बजाय वह फलों को काटकर खाने को देती हैं। इसके पीछे उनकी सोच है कि इससे बच्चा फलों के कलर व आकार आदि के बारे में भी समझता है और मन लगाकर खाता भी है। हल्दी-दूध (गोल्डन मिल्क) को रूटीन में शामिल कर लिया है ।

परिवार के हर सदस्य का टीकाकरण जरूरी :आलमबाग निवासी अर्शिया अपनी आठ साल की बेटी को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित बनाने के लिए सबसे पहले तो परिवार के सभी सदस्यों के कोविड टीकाकरण पर जोर दे रही हैं ताकि वायरस घर तक न पहुँच सके । उनका मानना है कि अभी बच्चों का टीका तो आया नही है इसलिए वायरस से लड़ने के काबिल उन्हें बेहतर पोषण और जरूरी एहतियात बरतकर ही बनाया जा सकता है। इसमें उनका साथ पूरा परिवार भी दे रहा है

नियमित टीके का रखें ख्याल : इंदिरानगर की दीपा अपनी तीन माह की बेटी के जरूरी टीके के बारे में बराबर सजग रहती हैं । उनकी सभी से अपील भी है कि इस कोरोना काल में भी बच्चे के नियमित टीकाकरण का पूरा ख्याल रखें । नियमित लगने वाले टीके बच्चों को बीमारियों से बचाने के साथ ही उनसे लड़ने की ताकत भी देते हैं और उन्हें स्वस्थ रखने में भी मददगार हैं।

फास्ट फूड से बना लें दूरी : गोमतीनगर निवासी भावना तिवारी अपनी छह साल की बेटी और दो साल के बेटे को फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रखती हैं। एसजीपीजीआई में कार्यरत भावना इसके अलावा बच्चों को कोल्डड्रिंक आइसक्रीम व ठंडी चीजों को बिल्कुल खाने को नही देती क्योंकि वह उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

योग और इनडोर गेम पर रहता है जोर : राजाजीपुरम निवासी ऋतिका श्रीवास्तव अपनी सात साल की बेटी और पांच साल के बेटे को योग और इनडोर गेम में व्यस्त रखती हैं ताकि वह मानसिक रूप से परेशान न हों और उनमें गुस्सा व चिड़चिड़ापन न आने पाए । इससे बच्चों का घर पर मन लगा रहता है और वह बाहर जाने की जिद भी नहद्व करते हैं । वह खुद योग करती हैं और बच्चों को भी उसे करने के लिए प्रेरित करती हैं।

कोविड सम्बन्धी किसी भी आपात स्थिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर- **1075,** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बच्चों के हेल्पलाइन नम्बर **1098** और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी समस्या के लिए निम्हंस के हेल्पलाइन नम्बर **08046110007** पर संपर्क किया जा सकता है ।

वाजपेयी ने जब दिलीप कुमार को थमा दिया था फोन, पाक पीएम नवाज शरीफ को खूब लगाई थी फटकार

ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार आज हमारे बीच नही रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे दिलीप कुमार ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ९८ वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार भारत के ही नही बल्कि दुनिया भर के चहेते अभिनेता थे। दिलीप कुमार का जन्म स्थान भले ही आज पाकिस्तान की सरहद के भीतर हो, लेकिन दिलीप साहेब का दिल हिंदुस्तान में बसता था।

पाकिस्तान की हरकतों से दिलीप बेहद नाराज थे, लेकिन १९९९ में जब पाकिस्तान ने कारगिल में भारत पर हमला किया तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। इससे जुड़ा एक किस्सा काफी चर्चित भी हुआ था। दरअसल दिलीप कुमार की भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से गहरी दोस्ती थी। १९९९ में कारगिल युद्ध के बाद एक बार नवाज शरीफ से बात करते वक्त वाजपेयी ने अचानक फोन अपने पास ही बैठे दिलीप कुमार को थमा दिया था। फिर क्या था दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने शरीफ को शराफत में रहने की सलाह दे डाली।

नवाज शरीफ और दिलीप कुमार के बीच हुई इस गर्मागमी का जिक्र पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अपनी किताब श्नाइदर अ हॉक नॉर अ डवश् में भी किया था। किताब के मुताबिक, एक दिन नवाज शरीफ के पास भारत के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से फोन आया। वाजपेयी ने नवाज शरीफ से कहा कि श्मुझे आपने लाहौर बुलाया। गले मिलकर स्वागत किया और अब देश के साथ ऐसा कर रहे हैं।नवाज शरीफ को वाजपेयी के इन शब्द बाणों का जवाब नहद्व सूझा तो उन्होंने कहा कि श्आप किस बारे में बात कर रहे हैं मैं आपकी बात आमी चीफ से करवाता हूं।श् नवाज शरीफ फोन काटते इससे पहले ही वाजपेयी ने उनसे कहा कि श्मुझे आपसे किसी की बात करवानी है।श् अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन दिलीप कुमार को थमा दिया। उस वक्त दिलीप कुमार वहीं थे। दिलीप कुमार की बातें सुनकर नवाज शरीफ भी हैरान रह गए।

फोन पर दिलीप कुमार ने नवाज शरीब को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि श्साहब आप हमेशा भारत-पाकिस्तान के बीच शांति के मुद्दे पर अडिग रहे हैं आप ऐसा करेंगे ऐसी उम्मीद नहद्व थी। दोनों देशों के बीच के तनाव के चलते भारत में मुसलमान अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए कुछ कीजिए।

हर परिवार के एक शख्स को मिलेगी सरकारी नौकरी? जानिए- क्या है सच्चाई

नई दिल्ली (आईएनआईएस) बड़ी संख्या में युवाओं का सपना होता है कि वह सरकारी नौकरी करें। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे में कुछ लोग सरकारी नौकरियों से जुड़ी अफवाहें भी फैला रहे हैं। दरअसल,

एक यूट्यूब चौनल पर दावा किया गया है कि केंद्र सरकार हर परिवार से एक शख्स को सरकारी नौकरी दे रही है।

लेकिन, क्या यह दावा सही है? इसी सवाल की खोज के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक विंग ने इस दावे की पड़ताल की। च्ठ की फैक्ट चेक विंग ने इस दावे की भी जांच की। जांच में पता चला कि दावा फेक है। च्ठ फैक्ट चेक ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकार दी। पीआईबी की फैक्ट चेक विंग ने/पीआईबी फैक्ट चेक से ट्वीट किया, 'दावा' एक यूट्यूब चौनल पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 'एक परिवार एक नौकरी योजना' के तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पीआईबी फैक्ट चेक यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

गौरतलब है कि पीआईबी की फैक्ट चेक विंग सरकार या उसकी योजनाओं से जुड़ी संदेहपूर्ण खबरों का फैक्ट चेक करती है। पीआईबी की यह विंग सरकार, सरकारी योजनाओं, राष्ट्र और लोगों के हितों से जुड़े तथ्यों, जानकारियों, दावों और अफवाहों की पड़ताल करती है।

अगर आपको भी केंद्र सरकार की नीतियोजना से जुड़ी किसी खबर या दावे में कोई संदेह है तो आप भी च्ठ की फैक्ट चेक विंग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें /पीआईबी फैक्ट चेक पर ट्वीट, ८७६६७११२५६ पर व्हाट्सएप और pibfactcheck@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

इन दिनों एक ऐप काफी चर्चाओं में है जिसका नाम सुली डील्स एप है।

नई दिल्ली (आईएनआईएस) इन दिनों एक ऐप काफी चर्चाओं में है जिसका नाम सुली डील्स

एप है। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की जानकारी साझा करने को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने स्वतरू संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मीडिया में ये खबरें आने के बाद आयोग ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस से कई डिटेल्स मांगी गईं हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को १२ जुलाई तक का वक्त दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है।

इस ऐप का पता हाल ही में चला जब लोगों ने ट्विटर पर डील्स ऑफ द डे शेयर करना शुरू किया। इस ऐप में मुस्लिम महिलाओं की नाम, फोटो और सोशल मीडिया प्रोफाइल शेयर की जा रही हैं। इसमें महिलाओं के नाम के आगे कीमत भी लिखी गई थी। इसमें ८० से ज्यादा महिलाओं की तस्वीर उनके नाम के साथ डाली गईं थी। इस ऐप को गिटहब नाम के ओपन सोर्स प्लैटफॉर्म पर बनाया गया था जिसमें टॉप पर लिखा था फाइंड योर सुल्ली डील। जैसे ही इस पर क्लिक किया जाता तो एक मुस्लिम महिला की फोटो, नाम और ट्विटर हैंडल की डिटेल्स सामने आ जाती थी। फिलहाल इसे गिटहब से हटा दिया गया है। वही, एक शिकायत मुंबई पुलिस में भी की गई है। जवाब में साकीनाका पुलिस स्टेशन की ओर से ट्विटर इंडिया और गिटहब को चिट्ठी लिख कर ऐप बनाने वाले और इसे ट्विटर पर शेयर करने वालों की जानकारी मांगी है। गिटहब से पुलिस ने आईपी एड्रेस, लोकेशन और ऐप कब बना हैं- इसकी जानकारी मांगी है। साथ ही ऐप को बनाने में इस्तेमाल होने वाला इमेल आईडी और फोन नंबर भी मांगा है। इसके अलावा ट्विटर से कुछ आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट करने और उस हैंडल को चलाने वाले लोगों का डेटा मांगा गया है।

जम्मू-कश्मीर में २०११ की जनगणना पर होगा परिसीमन, बढ़ाई जाएंगी ७ सीटें

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पर बने परिसीमन आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में २०११ जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। सुशील चंद्रा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में सात सीटें और बढ़ाई जाएंगी इनमें एसटी कोटे की सीट भी होंगी।

जम्मू-कश्मीर के परिसीमन पर वहां के दौरे के बाद जम्मू में प्रेस वार्ता के दौरान सुशील चंद्रा ने कहा कि आयोग ने जम्मू-कश्मीर के सभी जिला अधिकारियों से मुलाकात की है और सभी अधिकारियों ने उन्हें कई परिसीमन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं। वर्ष १९६५ में जम्मू-कश्मीर में १२ ही जिले होते थे लेकिन अब वहां पर जिलों की संख्या को बढ़ाकर २० कर दिया गया है और साथ में तहसीलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। परिसीमन आयोग के सदस्य सुशील चंद्रा ने पत्रकारों को यह भी बताया कि अगले साल मार्च तक जम्मू-कस्मीर का परिसीमन पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और परिसीमन के लिए २०११ की जनगणना को आधार माना जाएगा। उन्होंने बताया कि परिसीमन की कठिन लेकिन जरूरी प्रक्रिया में ७ अतीरिक्त सीटें जोड़नी है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी जम्मू-कश्मीर विधानसबा में २४ अलग सीटें होंगी। जम्मू-कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल वहां पर परिसीमन से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद वहां पर विधानसभा चुनाव कराए जाएं और उसके बाद परिसीमन की कार्रवाई हो।

विश्व जनसंख्या दिवस विशेष, परिवार नियोजन की अलख जगाएंगे पंचायत प्रतिनिधि

परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सही मायने में धरातल पर उतारने को लेकर हर स्तर पर हरसंभव प्रयास निरंतर जारी हैं ताकि लोगों को 'छोटे परिवार के बड़े फायदे' की बात आसानी से समझाई जा सके । इस बारे में बड़े पैमाने पर जनजागरूकता के उद्देश्य से ही हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसँख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर मथुरा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल की है, जिसका जिक्र करना लाजिमी है। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र जारी कर घर-घर परिवार नियोजन की अलख जगाने की अपील की गयी है। ग्राम प्रधानों ने भरोसा जताया है कि वह लोगों को इस बारे में जागरूक करने का हरसंभव प्रयास करेंगे ।

मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रचना गुप्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर कोरोना से बचाव के साथ परिवार नियोजन कार्यक्रमों में भी मदद की अपील की गयी है । पत्र में जिक्र है कि पंचायत प्रतिनिधियों की गाँव के विकास में अहम् भूमिका है लेकिन बिना परिवार नियोजन के हम सही अर्थों में विकास के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिए आइये हम सभी "परिवार नियोजन जीवन बचाता है " मूल मन्त्र को ध्यान में रखते हुए यह

प्रण करें कि कोविड-19 के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी केंद्र व

राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (यूपी टीएसयू) के साथ मिलकर कार्य करेंगे । कोरोना को देखते हुए ही इस बार विश्व जनसँख्या दिवस पखवारे की थीम "आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी" तय की गयी है।

मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल का कहना है कि विश्व जनसँख्या दिवस के जरिये परिवारों की बढती आबादी, लिंग असमानता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गरीबी, मानवाधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, यौन शिक्षा, निरोधकों और कंडोम, प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, गर्भावस्था, बालिका शिक्षा, बाल विवाह, यौन संचारित संक्रमण और सुरक्षा उपायों का उपयोग आदि के बारे में जनजागरूकता लायी जाती है ।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. नितिन गौड़ का कहना है कि प्रदेश में उपलब्ध विकास के संसाधनों का समुचित वितरण और बढती जनसँख्या दर के बीच संतुलन बनाने के लिए जनसँख्या स्थिरीकरण आज के समय की सर्वाधिक आवश्यकता है। इसके लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में इन सेवाओं व सुविधाओं को प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को भी हौसला साझीदारी के माध्यम से इस मुहिम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रचना गुप्ता का कहना है कि जिले में 27 जून से 10 जुलाई तक दम्पति संपर्क पखवारा चलाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लक्ष्य दम्पति की सूची तैयार की है और लोगों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अब 11 से 31 जुलाई तक सेवा प्रदायगी पखवारा मनाया जाएगा और अंतराल विधियों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा । इस कार्य में यूपी टीएसयू के साथ ही सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार), जननी और पीएसआई टीसीआईएचसी समेत कई अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं भरपूर मदद पहुंचा रहीं हैं ।

- मथुरा जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल
- संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर मांगी मदद
- मुखिया ने कहा- हर किसी को बताएँगे छोटे परिवार के बड़े फायदे

से जोड़ा गया है। विकास खंड बलदेव के हथकौली गाँव के प्रधान काली चरण का कहना है कि 11 से 31 जुलाई तक चलने वाले जनसँख्या स्थिरता पखवारे के दौरान वह आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर लक्षित दम्पति तक पहुंचकर उन्हें परिवार नियोजन की सेवाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे । परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास होगा । पुरुष नसबंदी को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें दूरकर जिनका परिवार पूर्ण हो गया है, उन लोगों को नसबंदी के लिए प्रेरित करेंगे।

सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध सेवाएं :

- स्थायी विधि- महिला व पुरुष नसबंदी
- अस्थायी विधि - ओरल पिल्स, निरोध, आईयूसीडी प्रसव पश्चात गर्भ समापन पश्चात् आईयूसीडी, गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा व हार्मोनल गोली छाया (सैंटोक्रोमान)

विश्व जनसँख्या दिवस की शुरुआत :

विश्व जनसँख्या दिवस के आयोजन पर 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी के पांच अरब पहुँचने पर विचार किया गया था । इस दिवस के आयोजन के बारे में विश्व बैंक के सीनियर डेमोग्राफर डॉ. के. सी. जकरिया द्वारा सुझाया गया था। यह आयोजन वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसल द्वारा स्थापित किया गया था।

-शशिधर द्विवेदी

यूपी में कोरोना के कप्पा वैरिएंट के पहले मरीज ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप

लखनऊ (एस.एन.लाल) देवरिया और गोरखपुर में डेल्टा प्लस स्ट्रेन के दो मामले पाए जाने के बाद अब संत कबीर नगर में एक मरीज कोविड-१९ के कप्पा स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है। ६६ वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। जीनोम अनुक्रमण अभ्यास के दौरान स्ट्रेन का पता चला था। उनका नमूना १३ जून को नियमित रूप से इक्ट्ठा किया गया था और सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, नई दिल्ली को भेजा गया था, जिसने नमूने में कप्पा स्ट्रेन की पुष्टि की है।

डेल्टा प्लस की तरह, कप्पा को भी चिंता का एक रूप घोषित किया गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख अमरेश सिंह ने कहा कि मरीज ने २७ मई को कोविड का परीक्षण किया था और उसे १२ जून को मेडिकल कॉलेज लाया गया था। १३ जून को सैंपल लिया गया था।

सिंह ने कहा, ९१४ जून को इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहद्र थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि राज्य से जीनोम अनुक्रमण के लिए २,००० से अधिक नमूने भेजे गए हैं। इस सप्ताह उत्तर प्रदेश में पहली बार डेल्टा प्लस स्ट्रेन के दो मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि तीनों रोगियों में से किसी का भी यात्रा इतिहास नहद्र था, इससे पता चलता है कि राज्य में वायरस उत्परिवर्तित हो रहा है।

सम्पादकीय

युवाओं की क्षमता का दोहन

भारत में ६२प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की आयु १५ से ५६ वर्ष के बीच है तथा जनसंख्या की औसत आयु ३० वर्ष से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत जनसंख्या की आयु संरचना के आधार पर आर्थिक विकास की क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाले श्जनसांख्यिकीय लाभांश के चरण से गुजर रहा है।

हालाँकि इस क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिये किशोरों और युवाओं को स्वस्थ एवं सुशिक्षित होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश पर एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर वर्ष २००५-०६ से वर्ष २०५५-५६ तक ५ दशकों के लिये उपलब्ध है। इसलिये 'जनसंख्या विस्फोट' की आशंका से अधिक यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत युवा जनसंख्या की स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करे क्योंकि भारत का कल्याण इसी पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है, 'आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप प्राप्त हो सकती है, मुख्यतः जब कार्यशील उम्र की आबादी (१५ से ६४ वर्ष) का हिस्सा गैर-कार्यशील उम्र (१४ और उससे कम, तथा ६५ एवं उससे अधिक) की आबादी से बड़ा हो'।

शिक्षा और कौशल की कमीरू भारत की अल्प-वित्तपोषित शिक्षा प्रणाली युवाओं को उभरते रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिये अपर्याप्त है। विश्व बैंक के अनुसार, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय वर्ष २०२० में सकल घरेलू उत्पाद का केवल ३.४प्रतिशत था। एक अन्य रिपोर्ट से पता चला है कि प्रति छात्र सार्वजनिक व्यय के मामले में भारत ६२वें स्थान पर है और छात्र-शिक्षक अनुपात एवं शिक्षा उपायों की गुणवत्ता में इसका प्रदर्शन खराब रहा है।

महामारी का प्रभावरू विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा, जीवन और मानसिक कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि दुनिया भर में महामारी के दौरान ६५प्रतिशत किशोरों की शिक्षा में कमी आई है। युवा महिलाओं के मुद्दे : बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, दुर्व्यवहार और तस्करी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, खासकर यदि प्राथमिक देखभाल करने वाले बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं जैसे मुद्दे युवा महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं।

रोजगार विहीन विकासरू भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदानकर्त्ता सेवा क्षेत्र है जो श्रम प्रधान नहद्र है और इस प्रकार यह रोजगार विहीन विकास को बढावा देता है इसके अलावा भारत की लगभग ५०प्रतिशत आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है जो कि अल्प-रोजगारऔर प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिये बदनाम है।

निम्न सामाजिक पूंजीः इसके अलावा उच्च स्तर की भुखमरी, कुपोषण, बच्चों में बौनापन, किशोरियों में रक्ताल्पता का उच्च स्तर, खराब स्वच्छता आदि ने भारत के युवाओं की क्षमता को साकार करने में बाधा पहुँचाई है। अंतर-क्षेत्रीय सहयोगरू युवा पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा के लिये बेहतर अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिये एक तंत्र का होना अनिवार्य है। विभागों के बीच समन्वय किसी भी संकट से निपटने के लिये बेहतर समाधान और अधिक क्षमता को सक्षम कर सकता है।

उदाहरणतः मध्याह्न भोजन योजना न केवल माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है बल्कि कक्षा में सतर्क रहने के लिये आवश्यक कैलोरी की मात्रा भी प्रदान करती है। युवा आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिये कौशल विकासरू भारत की श्रम शक्ति को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिये सही कौशल के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने वर्ष २०२२ तक भारत में ५०० मिलियन लोगों को कौशल युक्त करने के समग्र लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना की है।

सामाजिक बुनियादी ढाँचे में सुधारः यदि भारत अपने युवा उभार की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना चाहता है तो उसे सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसे- अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करने के लिये निवेश करना चाहिये और पूरी आबादी को अच्छा रोजगार प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये। बुनियादी स्वच्छता को बनाए रखनारू चूँकि स्कूल बंद होने से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता उत्पादों की किशोरों तक पहुँच जैसी योजनाएँ प्रभावित हुई हैं। बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिये फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को सहयोग करने हेतु शिक्षक स्वयंसेवकों के रूप में काम कर सकते हैं। युवाओं के लिये हेल्पलाइन : किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों को मौजूदा हेल्पलाइन के माध्यम से तथा उनके प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कर उन्हें सक्षम बनाया जाना चाहिये।

महामारी के बाद तत्काल कदमः लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के नुकसान के साथ बच्चों के माध्यम से महामारी के संचरण के जोखिम को संतुलित करना नीति निर्माताओं हेतु महत्त्वपूर्ण है। शिक्षकों और स्कूल के सहायक कर्मचारियों के टीकाकरण को प्राथमिकता देकर तथा एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ स्कूलों को सुरक्षित और चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है।

मिशन मोड में युवाओं के जीवन में सुधार करने से उनका जीवन उन्नत होगा, साथ ही स्वस्थ और शिक्षित युवा वयस्कों के चलते भारत के भविष्य को सुरक्षित करने में योगदान भी प्राप्त होगा। युवाओं के सशक्तीकरण की नीतियाँ और उनके प्रभावी कार्यान्वयन से जनसांख्यिकीय लाभांश, जो कि एक समय-सीमित अवसर है, भारत के लिये एक वरदान बन सके।

सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष अजित मोहन की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली। (आईएनआईएस) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा

की शांति एवं सौहार्द समिति की ओर से जारी सम्मन के खिलाफ फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अजित मोहन की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष अजित मोहन की याचिका को अपरिपक्व बताया और कहा कि विधानसभा समिति के समक्ष उनके खिलाफ कुछ नही हुआ है।

दरअसल, विधानसभा ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में मोहन को गवाह के तौर पर पेश होने के लिये कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहद्र किया। इसके बाद उन्हें सम्मन भेजे गए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने मोहन की याचिका को अपरिपक्व बताया और कहा कि दिल्ली विधानसभा के समक्ष उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। मोहन, फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फेसबुक इंक की याचिका पर यह निर्णय लिया गया है। याचिका में कहा गया था कि समिति के पास यह शक्ति नहद्र है कि वह अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन होने पर याचिकाकर्ताओं को तलब करे। यह उसकी संवैधानिक सीमाओं से बाहर है।

उन्होंने समिति द्वारा पिछले साल दस और १८ सितंबर को जारी नोटिस को चुनौती दी थी। इनमें मोहन को समिति के समक्ष पेश होने के लिये कहा गया था। समिति दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कथित भड़काउ भाषण फैलाने में फेसबुक की भूमिका की जांच कर रही है।

खेल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निकला वाहन, सरकार से है ये प्रमुख मांग

गाजियाबाद (आईएनआईएस) गाजियाबाद से एक खेल साक्षरता प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वाहन को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा भारत भ्रमण के लिए रवाना किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनजीओ स्पोर्ट्सरू ए वे ऑफ लाइफ द्वारा किया गया। संस्थआ के अध्यक्ष डॉ. कनिष्क पांडेय ने इस दौरान कहा कि देश में खेल साक्षरता महज ५ फीसदी है और महिलाओं के बीच तो यह मात्र २.५ फीसदी ही है। ऐसी स्थिति में लोगों को खेल साक्षर बनाएं बिना ओलंपिक मेडल की बात सोचना भी दूर की बात है।

उन्होंने कहा कि खेल साक्षरता प्रसार वाहन इस दिशा में एक पहल है जो गाजियाबाद से शुरू होकर देश के कई गांवों, कस्बों और जिलों से होते हुए यूपी

की राजधानी लखनऊ में खत्म होगी। इस दौरान रास्ते में गांव के बच्चों को लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। बच्चोंमें खेल साक्षरता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

आपको बता दें कि ये खेल प्रसार वाहन गाजियाबाद से हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर के रास्ते लखनऊ पहुंचेगा। खास बात ये होगी कि हर रात को ये वाहन किसी न किसी गांव में रुकेगा और वहां के बच्चों को खेलने से जोड़ने की कोशिश करेगा। इतना ही नहद्र, खेल प्रसार वाहन जिस भी जिले से गुजरेगा, वहां के डीएम को कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेगा, जिनमें से खेलकूद के लिए आरक्षित भूमि पर खेल की सुविधाएं विकसित करने की मांग अहम है।

कोरोना वायरस के लैम्बडा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है।

नयी दिल्ली (आईएनआईएस) भारत सहित दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बाद

अब कोरोना वायरस के लैम्बडा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि अबतक ३० से ज्यादा देशों में लैम्बडा वेरिएंट के मामले मिले हैं। वही भारत सरकार ने कहा कि भारत में अब तक सार्स-सीओवी-२ के लैम्बडा वेरिएंट का कोई मामला सामने नहद्र आया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि इंडियन सार्स-सीओवी-२ जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) स्वरूप पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा, ''१४ जून को डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा पहचाना गया लैम्बडा वायरस का सातवां वेरिएंट था और २५ देशों में इसका पता चला है।'' अग्रवाल ने कहा, ''हमारे देश में इसका कोई मामला सामने नहद्र आया है और आईएनएसएसीओजी इस पर नजर रख रहा है और हम सतर्क हैं। पेरू में, ८० प्रतिशत संक्रमण इसी स्वरूप के थे। यह दक्षिण अमेरिकी देशों और ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में भी मिला है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किसी भी प्रभाव की निगरानी की जाएगी।''

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल ने कहा कि लैम्बडा वेरिएंट पर ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''जहाँ तक हम जानते हैं कि इसने हमारे देश में प्रवेश नहीं किया है, अपने देश में यह नही मिला है। हमारी निगरानी प्रणाली आईएनएसएसीओजी बहुत प्रभावी है और अगर यह वेरिएंट देश में प्रवेश करता है तो वह इसका पता लगा लेगी।'' पॉल ने कहा, ''हमें इन प्रकार के वेरिएंट्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए।'' कोविड के कप्पा वेरिएंट के बारे में पॉल ने कहा कि यह स्वरूप फरवरी और मार्च में भी देश में मौजूद था और इसकी तीव्रता बहुत कम थी तथा डेल्टा वेरिएंट ने बड़े पैमाने पर इसका स्थान ले लिया है। उन्होंने कहा, ष्कप्पा वेरिएंट देश में फरवरी-मार्च में भी मौजूद था, डेल्टा वेरिएंट कप्पा के समान है। डेल्टा वेरिएंट के सामने आने पर यह दब गया था और हमारे देश में कुछ समय के लिए यह वेरिएंट (कप्पा) था। डेल्टा एक संबंधित वेरिएंट है और तेजी से फैल सकता है और यह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था।'' एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोविड-१९ के कप्पा स्वरूप के दो मामलों का पता चला है। लैम्बडा वेरिएंट, हालांकि अभी तक पूरी तरह से चिंता का वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसके उच्च संचरण क्षमता और म्यूटेशन फीचर्स इसे संभावित खतरे का कारण बना रहे हैं।

बालों को असमय सफेद होने से रोकती है लौकी, पढ़ें हेल्थ

लौकी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। इसका दूसरा नाम कद्दू व काशीफल भी है। इसका इस्तेमाल अक्सर सब्जी, बर्फी व रायता बनाने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के चिकित्सक डा. पीसी प्रसाद के मुताबिक थोड़ा सा कड़वा टेस्ट लिए हुए लौकी में बहुत सारे न्यूट्रिवेंट्स मौजूद होते हैं। इसलिए इसे ज्यादा पकाने से इसके न्यूट्रिवेंट्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। हेल्थ स्पेशलिस्ट लौकी के सेवन की सलाह कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में अक्सर लोगों को देते हैं।

लौकी खाने के फायदे

१. सुबह १ ग्लास लौकी का जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इससे बालों का असमय सफेद होने की दिक्कत से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।

२. भागदौड़ भरी जिदंगी में काम के टेंशन से बच पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही खराब खानपान इसे बिल्कुल दोगुना कर देती है। लौकी में मौजूद पानी की मात्रा बाडी को रिफ्रेश रखने का काम करती है, जिससे तनाव में बहुत राहत मिलती है, कई सारे न्यूट्रिवेंट्स शरीर को अंदरूनी रूप से बहुत स्ट्रांग रखते हैं, जिससे तनाव और चिंता जैसी प्राब्लम्स से बहुत राहत मिलती है।

३.कब्ज जैसी समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए लौकी खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमे मौजूद फाइबर पेट की अंदरूनी सफाई करता है। साथ ही एसिडिटी की प्राब्लम होने पर लौकी का जूस पीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है

४. लौकी खा कर शरीर को ठंडा रखा जा सकता है। साथ ही इसका जूस पेशाब करते समय हो रहे जलन की समस्या को भी बहुत दूर करता है

५ . लौकी का जूस पेट की अंदरूनी सफाई करता हैं, जिससे चेहरे पर धूप, धूल और पोल्यूशन से होने वेल कील-मुहांसे से बहुत जल्द छुटकारा मिलता है। साथ ही त्वचा खूबसूरत और कोमल भी बनी रहती है।

प्लास्टिक के बर्तनों में खाने-पीने से पुरुषों को हो सकती हैं गंभीर बीमारियां

रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में पाए जाने वाले हानिकारक रसायनों से पुरुषों में गंभीर बीमारियां होने की आशंका रहती है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, एडिलेड विश्वविद्यालय व दक्षिण आस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य एवं मेडिकल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने १,५०० से ज्यादा पुरुषों में थैलेट्स नामक रसायन की मौजूदगी की संभावना की जांच की है। यह रसायन दिल की बीमारी व उच्च रक्तचाप व टाइप-२ मधुमेह से जुड़ा है।

ए डि ले ड विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर जुमिन शी ने कहा कि परीक्षण किए गए पुरुषों में थैलेट्स की पहचान करीब हर (९९।६ फीसदी) ३५ साल व उससे ज्यादा आयु वाले लोगों के पेशाब के नमूने में पाया गया है। ऐसा प्लास्टिक के बर्तनों या बोतलों में रखे खाद्य पदार्थ को खाने से हुआ है।

शी ने एक बयान में गुरुवार को कहा, हमने ज्यादा थैलेट्स स्तर वाले पुरुषों में दिल संबंधी बीमारियां, टाइप-२ मधुमेह व उच्च रक्त दाब को बढ़ा हुआ पाया है। उन्होंने कहा, हम अभी भी थैलेट्स के स्वतंत्र रूप से बीमारी से जुड़े होने से सटीक कारण को नहीं समझ सके हैं। हम मानव अंतरूस्रावी प्रणाली पर रसायनों के प्रभाव को जानते हैं, जो हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करते हैं, जो शरीर के वृद्धि, उपापचय व लैंगिक विकास व कार्य को नियमित करते हैं।

शी ने कहा कि यह विशेष बात है कि पश्चिम के लोगों में थैलेट्स का स्तर ज्यादा है, क्योंकि वहां बहुत सारे खाद्य पदार्थो को अब प्लास्टिक में पैक किया जाता है।उन्होंने कहा कि पहले के शोध में पाया गया है कि जो साफ्ट ड्रिंक पीते हैं और पहले से पैक खाद्य सामग्री को खाते हैं, उनके पेशाब में स्वस्थ लोगों की तुलना में थैलेट्स की मात्रा ज्यादा पाई गई।

ज्यादा फैट वाला खाना खाने से हो सकता है बड़ी आंत का कैंसर

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) का कहना है कि खराब जीवनशैली और हानिकारक आहार से बड़ी आंत का कैंसर होने का खतरा होता है। अधिक वसा और कम रेशों वाले भोजन से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में कोलोरेक्टल कैंसर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। हर साल इसके १४ लाख नए मामले सामने आते हैं और ६।६४ लाख लोगों की इसके वजह से मृत्यु हो जाती है। भारत में इस तरह का कैंसर का मामला बढ़ने लगा है। प्रति तीन कोलोरेक्टल कैंसर मरीजों में एक मरीज में इसका स्थान मलाशय में होता है। आईएमए का मानना है कि अधिक वसा और कम रेशों वाले भोजन से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

आईएमए के अध्यक्ष डा. के.के. अग्रवाल ने कहा, अब तो कोलन या बड़ी आंत का कैंसर बच्चों में भी मिलने लगा है। एक ही जगह बैठे रहना, डेस्क जाब, अस्वास्थ्यकर भोजन आदि से इस कैंसर को बढ़ावा मिलता है। कम जानकारी के कारण, करीब ४० से ५० प्रतिशत मामले ही सामने आ पाते हैं, वो भी तब जब कैंसर अंतिम चरण में पहुंच चुका होता है।

उन्होंने कहा, मलाशय से रक्त स्राव, कब्ज और डायरिया दो दिन से अधिक रहे तो लोग उसे कुछ अन्य रोग समझ बैठते हैं। इससे कैंसर की जांच में विलंब होता जाता है। भारत का मूल आहार रेशेदार हुआ करता था, जो पाचन तंत्र के अनुकूल होता था। पश्चिमी आहार में प्रिजर्वेटिव अधिक होते हैं और रेशे कम होते हैं, जिससे न सिर्फ कोलन कैंसर, बल्कि अन्य कई रोगों का खतरा भी पैदा हो जाता है।

अग्रवाल ने कहा, इसके कुछ लक्षण हैं- दो सप्ताह से अधिक रहने वाला डायरिया या कब्ज, मल में रक्त या चिकनाई दिखाई देना, मलत्याग में कठिनाई, रक्ताल्पता, पेट में सूजन या निरंतर दर्द या असहज महसूस होना, अचानक वजन में कमी होते जाना, बहुत अधिक थकान, चक्कर आना या उल्टी करने की इच्छा होना।

उन्होंने बताया, समय रहते स्क्रीनिंग मददगार रहती है, क्योंकि प्रीकैंसरस प लिप को पहले ही खत्म कर दिया जाए तो वे कैंसर कोशिकाओं में नहीं बदल पातीं। बड़ी आंत की दीवार तक सीमित कैंसर सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के चलते, पांच प्रतिशत से कम मरीजों को ही कोलोस्टोमी की जरूरत होती है। यह मलत्याग के लिए एक नया मार्ग बनाने की सर्जरी होती है।

कोलन कैंसर के खतरे को कम करने के उपाय-

फल, सब्जियां और संपूर्ण अनाज का सेवन करें।

यदि मदिरापान करते हों तो कम ही करें। महिलाओं के लिए प्रतिदिन एक पैग और पुरुषों के लिए दो पैग से अधिक नहीं।

धूम्रपान करते हों तो बंद कर दें और इस कार्य में अपने चिकित्सक की मदद लें।

प्रतिदिन कम से कम ३० मिनट व्यायाम अवश्य करें।

वजन पर नियंत्रण रखें। जो पहले से ही मोटे हैं, वह व्यायाम और संतुलित आहार करें।

'आदमखोर कोशिकाएं' की मदद से वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर रोकने का नया तरीका

कैंसर की बढ़त रोकने में 'आदमखोर कोशिकाएं' मददगार हो सकती हैं। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन के नतीजों में यह उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि स्वस्थ कोशिकाओं को उनके आसपास मौजूद कैंसरग्रस्त कोशिकाओं के खात्मे के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस तरह इस घातक बीमारी के फैलने की गति धीमी की जा सकती है या उसको बढ़ने से रोका जा सकता है।

इंटोसिस की प्रक्रिया

शोधकर्ताओं ने बताया कि जो कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को मारकर खा जाती हैं उन्हें 'आदमखोर या स्वजातिभक्षी कोशिकाएं' (कैनिबल सेल) कहते हैं। जबकि कोशिकाओं के अन्य कोशिकाओं को खाने या मार डालने की प्रक्रिया को 'कोशिकीय स्वजाति-भक्षण' (सेल कैनिबलिज्म) कहा जाता है। कोशिकीय स्वजाति-भक्षण को वैज्ञानिक भाषा में इंटोसिस भी कहते हैं। यह दरअसल एक जीवित कोशिका का दूसरी कोशिका के जीवद्रव्य पर हमला होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इंटोसिस स्वस्थ कोशिकाओं के बीच आम तौर पर नहीं होती। लेकिन ट्यूमर की कोशिकाओं में यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

अनियंत्रित कोशिका विभाजन

ब्रिटेन के बैबराहम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि कोशिका विभाजन के जरिये कोशिकाओं में स्वजाति भक्षण की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। कोशिका विभाजन किसी एक कोशिका के विभाजित होकर दो स्वतंत्र कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया है। शोधकर्ताओं ने कहा, अनियंत्रित रूप से होने वाला कोशिका विभाजन ही कैंसर पैदा करता है। इससे यह पता चला कि कोशिकाओं में स्वजाति भक्षण को प्रेरित कर उनमें अनियंत्रित विभाजन को नियंत्रित किया जा सकता है।

मनुष्य की कोशिका पर प्रयोग रू

शोधकर्ताओं ने इस संभावना का पता लगाने के लिए मनुष्य की उपकला (एपिथैलियल) कोशिकाओं का परीक्षण किया। ये कोशिकाएं शरीर में कई सतहों का निर्माण करती हैं। मनुष्यों में होने वाले ८० प्रकार के कैंसर पैदा करने में भी इनकी भूमिका होती है। सामान्य तौर पर उपकला कोशिकाएं विभाजन के बाद भी अपने आसपास से मजबूती से जुड़ी रहती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन कोशिकाओं का जुड़ाव कमजोर कर देने से इनमें इंटोसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई।

जिम्मेदार प्रोटीन की पहचान

शोधकर्ता जो डुर्गन ने कहा, हम ट्यूमर कोशिकाओं में इंटोसिस के लिए जिम्मेदार प्रोटीनों की पहचान करना चाहते थे। इसलिए हमने माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर ट्यूमर कोशिकाओं में इंटोसिस की प्रक्रिया की पूरी पड़ताल की। यह बिल्कुल अप्रत्याशित और नई चीज थी। उन्होंने कहा, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में हमने जिन सूत्रों की पहचान की वे कैंसर को रोकने के संदर्भ में वाकई दिलचस्प हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, इस खोज से पता चला कि विभाजित हो रही कोशिकाएं अपेक्षाकृत आसानी से अन्य कोशिकाओं द्वारा खत्म की जा सकती हैं। इससे साफ है कि इंटोसिस की प्रक्रिया के जरिये कैंसर कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं के जरिये नष्ट कराया जा सकता है। यह अध्ययन ई-लाइफ जर्नल

Obstructive Sleep Apnea Worsens Non-Alcoholic Fatty Liver Disease In Obese Adolescents

Shikha Sundaram, MD, MSC, associate professor of pediatrics, and her fellow researchers from the University of Colorado Anschutz Medical Campus studied 36 adolescents with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), along with 14 lean patients, to assess whether sleep apnea and low nighttime oxygen promoted the progression of the disease. The children eligible for the study were at the Children's Hospital Colorado Pediatric Liver Center between June 2009 and January 2014.

'Obese adolescents with obstructive sleep apnea and hypoxia had more severe scar tissue in their livers than those without sleep apnea and hypoxia.'

"There is emerging evidence that obesity-related obstructive sleep apnea and intermittent nocturnal hypoxia are associated with progression of non-alcoholic fatty liver disease," said Sundaram, whose study was published online in the Journal of Hepatology this month and appears in the September 2016 issue of the journal.

NAFLD is the accumulation of extra fat in liver cells in people who are overweight and who drink little or no alcohol. It is a disease of epidemic proportions that is increasing worldwide in both adults and children. It is estimated to affect up to 30 percent of the general population in western countries and up to 9.6 percent of all children.

In this study, investigators found that patients with obstructive sleep apnea and hypoxia, which is when the body is deprived of adequate oxygen supply, had more severe scar tissue in their livers than those without sleep apnea and hypoxia, driven by an imbalance of oxidative stress.

By recognizing that sleep-disordered breathing is an important trigger of the stress on the liver, follow-up investigations can focus on whether therapy, such as nighttime continuous positive airway pressure (CPAP), may reduce the harm caused by sleep apnea and hypoxia.

Complete Health Care Under One Roof

KHUSHI MEDICAL CLINIC & RESEARCH CENTRE

Dr. Dwivedi's

KHUSHI MEDICAL & RESEARCH CENTER

(A Multi-Speciality Medical-Health Center)

SHOP-15/107, 15/25, Ganesh Market, , Near C-Block Chauraha, Opposite Hanuman Mandir, Indira Nagar, Lucknow-226016

Phone : 9450097512 * 8090111100

E-mail: kmrc.india@gmail.com

PATHOLOGY

Dr Lal PathLabs

भारत का सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय पैथालाजी नेटवर्क

HOMEOPATHY

Khushi Homeopathic Clinic & Research Center

Lucknow's Best Homeopathic Research Center for Chronic Diseases

PHYSIOTHERAPY

Khushi Physiotheraphy Clinic & Research Center

Finest Physiotherapy Clinic with Modern Machines and Complete Rehabilitation

Homeopathic Consultation • Pathology • Physiotherapy

Homeopathic Pharmacy • Diagnostics • Health Check-ups

Study Finds Possible Link Between Unhealthy Pregnancy Diet & ADHD

The research, led by scientists from King's College London (KCL) and the University of Bristol and published in the Journal of Child Psychology and Psychiatry, this study is the first to indicate that epigenetic changes evident at birth may explain the link between unhealthy diet, conduct problems and ADHD.

'Promoting a healthy prenatal diet may lower ADHD symptoms and conduct problems in children.'

Early onset conduct problems (e.g. lying, fighting) and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) are the leading causes of child mental health referral in the UK. These two disorders tend to occur in tandem (more than 40% of children with a diagnosis of conduct disorder also have a diagnosis of ADHD) and can also be traced back to very similar prenatal experiences such as maternal distress or poor nutrition.

In this new study of participants from the Bristol-based 'Children of the 90s' cohort, 83 children with early-onset conduct problems were compared with 81 children who had low levels of conduct problems. The researchers assessed how the mothers' nutrition affected epigenetic changes (or DNA methylation) of IGF2, a gene involved in fetal development and the brain development of areas implicated in ADHD - the cerebellum and hippocampus. Notably, DNA methylation of IGF2 had previously been found in children of mothers who were exposed to famine in the Netherlands during World War II.

The researchers found that poor prenatal nutrition, comprising high fat and sugar diets of processed food and confectionary, was associated with higher IGF2 methylation in children with early onset conduct problems and those with low conduct problems.

Higher IGF2 methylation was also associated with higher ADHD symptoms between the ages of 7 and 13, but only for children who showed an early onset of conduct problems.

Dr Edward Barker from King's College London said "Our finding that poor prenatal nutrition was associated with higher IGF2 methylation highlights the critical importance of a healthy diet during pregnancy."

Diet can affect a range of psychiatric problems. There is good evidence that diet can affect depression and obesity. These results suggest that promoting a healthy prenatal diet may ultimately lower ADHD symptoms and conduct problems in children. This is encouraging given that nutritional and epigenetic risk factors can be altered.

He stressed that parents with children with ADHD should not blame themselves because diet was just one factor, albeit a potentially significant one. ADHD/conduct problems are very complex psychiatric problems, they are multi-determined. Diet could be an important but it is going to be important alongside a host of other risks. A sensible diet can improve symptoms but it is not a single causal agent.

Dr Barker added, "We now need to examine more specific types of nutrition. For example, the types of fats such as omega 3 fatty acids, from fish, walnuts and chicken are extremely important for neural development."

It is known that nutritional supplements for children can lead to lower ADHD and conduct problems, so it will be important for future research to examine the role of epigenetic changes in this process.

The results did not prove causation and needed to be replicated in larger studies, but added to a weight of evidence about the importance of diet for good mental health.

Social Media Rules For Making Your Presence Count

"Today, if you have a business, it is imperative to have a social media presence. Social media marketing allows people in business to build a relationship with their loyal customers, find new clients, and most importantly,it helps you stand out from the rest in the market."

Here's a detailed breakdown of some top rules to follow for building your social media presence from scratch.

Choose Your Platform : Although social media platforms are abundant on the internet, there is no need for you to venture into every single one of them. It would be best to begin with one or two social media platforms-only those that hosts a majority of your target demographics. Going all guns blazing right at the beginning will only abandon all the different accounts in the future. Once the accounts are live, invest your time and creativity in the social media accounts to sustain and eventually grow.

Craft Your Profiles : Social media offers a promising opportunity for people in business to expand their reach online. However, just creating accounts on the platforms won't be enough. Hence, you must try establishing a signature or a niche on your social media accounts. This will help you establish a brand for yourself in the online market, thereby setting you apart with clear distinction and style. Try aincorporating graphics into all your social content. Furthermore, you must maintain a sense of consistency with the style that you use across all your content. Additionally, social media brings SEO search ranking into the picture as well.

Post Consistently : Social media inclines us to live in the moment. Maintaining a content publishing streak will contribute to gathering new leads and retaining existing consumers. Until you have established a stable consumer base, you must refrain from any inconsistent social media activity.

Your activities and engagements will directly influence your social media presence-it could be daily, weekly or even on a fortnight basis. Your frequency will be depending on the traits of your business.

Respond To Engagement : If you plan to establish yourself as a social media personality or aim to extend your business beyond the existing boundaries, you must make sure you have a cordial relationship with your consumer base. Your social media pages should project a festive and community atmosphere for the visiting traffic to notice at first glance. Additionally, you must engage and acknowledge your existing consumers when they react to your content, product and services. It would be best if you leveraged your social media engagements to build on relationships with the audience.

Final Thoughts : Creating a brand for you on social media platforms is hard in this day and age. However, it would be best if you held the patience to ride out the tide to meet the rewards eventually. And with the above-listed rules, you can achieve an active social media presence to bring success and recognition to your business.

"Animesh Sharma is an ardent digital marketing and social media expert, consultant, author, speaker and trainer who helps companies grow their business; and also mentors a digital marketing agency DigitalWala. He regularly maintains his blog www.animeshsharma.com"

Bollywood Actress Sunny Leone, the Brand Ambassador of Newly Launched Energy Drink

Gold Fogg is set to mark its place as it is developed as a perfect answer to refresh, energize and revitalize an individual's busy lifestyle. True to its tagline, 'Live Your Way', Gold Fogg is a new and healthy drinking habit. The semi carbonated health drink is said to boost high energy levels and renewed zest. 'Gold Fogg is a ready-to-serve, alcohol-free energy drink for everyone who wishes to lead an on-the-go, healthy lifestyle.'Also, it is rich in vitamins and endowed with handpicked ingredients and extracts known for their energizing qualities. Besides offering a reservoir of energy, it has a proven effect on physical and intellectual performance of our body.

Mr. Rahul Vinakiya, Managing Director, R Z International Pvt. Ltd. said, "Gold Fogg is not just an energy drink; it is an experience, a treat to the mind, body and soul. With its unique and premium taste, we are sure Gold Fogg will make its presence felt in everyone's daily life, young and old, and revolutionize the energy drinks space." Gold Fogg, a 250ml, ready-to-serve, alcohol-free energy drink is for the young and the younger at heart, for college goers, sports enthusiast and champions, office professionals, avid gymers and everyone who wishes to lead an on-the-go, healthy lifestyle. Sunny Leone, said, "I am grateful to be associated with Gold Fogg. I personally love every sip of it and start my day with the fresh feel of Gold Fogg. It is just the right thrust of energy for all the upbeat and active people out there and I am sure everyone will love it as much as I do." R Z International are also manufacturers of of Mineral Water, Juices & Soft Drinks, Apple Juice, Energy Drink Gold Fott, Fruits Juice & Kiyy Juice, Gold Fogg is being manufactured and packed in India, Poland & Dubai.

Case Workers Need More Holistic Approach to Respond to Chronic Child Neglect

While the typical CPS response often focuses on a single case, which might not appear to be a matter of egregious harm, previous reports may provide a more comprehensive assessment of the situation. 'Child Protective Services caseworkers need to use a more all-encompassing approach to improve how they respond to cases of chronic neglect.'

"It's difficult to incorporate past allegations of neglect when you're looking at one incident that may not rise to a level of serious concern," says Annette Semanchin Jones, an assistant professor in the UB School of Social Work, who conducted the research with Patricia Logan-Greene, also an assistant professor of social work at UB.

Their recently published study, which appears in the journal Children and Youth Services Review, suggests that a more holistic approach might improve how CPS responds to cases of chronic neglect. "For cases of chronic neglect, if workers look over time and consider past allegations more thoroughly they could see an accumulation of harm that is very concerning," says Semanchin Jones.

There is no uniform definition of neglect. Its meaning can change depending on state standards but, generally, neglect is defined as failing to provide children with adequate food, clothing, shelter, medical care, education and supervision based on their age and development. Chronic neglect, which also has different definitions from state to state, is recurring cases of neglect within a family, often across multiple developmental stages for children. Despite its' prevalence, neglect is understudied and poorly understood from a research perspective, but Semanchin Jones says there is a growing body of literature that indicates how neglect, and chronic neglect in particular, can have serious consequences on a child's emotional regulation and cognitive development.

The UB study is among the first to examine cases of chronic neglect with a focus on CPS practices. The authors conducted a detailed case record review to examine CPS practices related to cases of chronic neglect, studying 38 families that had five or more neglect reports to CPS. The results found that all of the families had at least four significant stressors, including extreme poverty, parental substance abuse, parental mental health issues, child behavioral problems or domestic violence.

"This is a finding in itself," says Semanchin Jones. "Systems need workers trained to identity these issues. Having good training in place would give workers a foundational knowledge to identify these family challenges early on in the case. But the researchers found that case workers sometimes missed evidence of some of these risks. There were questions raised about risk assessment procedures. We saw evidence that the standardized processes used for risk assessment didn't always match the case notes." She says better training and implementation of risk assessment protocols may be needed to ensure assessment tools are being used correctly and consistently. "There needs to be a comprehensive assessment if there is any indication a family is experiencing chronic neglect," says Semanchin Jones. "Case workers need the tools to look at the history of the case, not just at one incident or one child, but at the whole family." A comprehensive assessment can help identify a family's strengths and challenges."

They're dealing with multiple factors. The initial assessment needs to be comprehensive so case workers can respond appropriately," she says. Logan-Greene added, "Building on these findings, the jurisdiction that was the focus of the study has already made some adjustments to better respond to the needs of these families, including specialized CPS teams with additional training on these issues related to chronic neglect."

LGBT Couples Get Limited Educational Information for Assisted Reproductive Technology

This disparity has implications for LGBT couples as more marry and begin or expand their families with ART.

'There is unequal online availability of educational materials regarding assisted reproductive technology (ART) tailored for lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) patients.'

The study, which appears in the journal Human Reproduction, is the first to systematically examine the prevalence of online health care information tailored for LGBT patients and suggests a potential gap in access to fertility services by LGBT persons as compared to the overall patient population.

The researchers reviewed the websites of all Centers for Disease Control and Prevention (CDC) registered fertility center websites in 2014 and again in 2015. The prevalence of information targeted to LGBT patients was compared to the prevalence of information targeted to heterosexual patients. The researchers found the majority of fertility clinic websites with patient education for heterosexual couples do not have similar materials for LGBT couples.

"Differential healthcare access impacted by sexual orientation or gender identity in the fertility setting add to healthcare disparities between LGBT patients and the overall patient population," explained corresponding author Shoumita Dasgupta, associate professor of medicine at Boston University School of Medicine. "As part of adapting to constantly changing societal and practice environments, addressing these disparities to provide culturally competent care should become a high priority initiative for practitioners in this area," she added.

According to the researchers developing these educational materials is a relatively straightforward initiative that can have many positive effects for inclusion of LGBT persons in fertility practices

With Best Compliments from :

NIDHISH MEDICALS

S-15/10, Ganesh Market, Indiranagar, Lucknow.

Ph.:9415797272

SHIVA MEDICALS

We stock & Sale Quality Medicine

S-15/8, Ganesh Market
Near Hanuman Mandir
Indiara Nagar,
Lucknow - 226 016

Cell : 9935832385

Sadbhawana Hospital

Sarvoday Nagar, Lucknow.

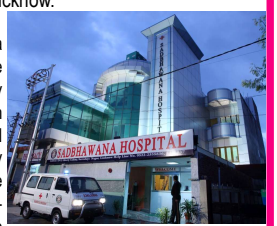

"Multispecialty" Sadbhawana Hospital is a landmark tertiary care health destination managed by highly experienced group. First of its kind in Lucknow, the 50+ bedded hospital has the state-of-the-art technology over virtually all specialties. The technology advantage is complemented by the man power excellence providing sophisticated and specialized medical care at affordable cost. With a team dedicated in bringing you a world of care with every visit. "World-class medical care, friendly, devoted service and affordability are the key features in our every touch."

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक अम्बरीश द्विवेदी द्वारा यज़्दा ए काम्यूनीकेशन ग्रुप, ३३६ प्रिन्स काम्प्लेक्स, हज़रतगंज, लखनऊ से मुद्रित एवं सी-६६५, इन्दिरा नगर, लखनऊ से प्रकाशित किया। RNI No.: UPBIL/2012/46720
सम्पादक : *अम्बरीश द्विवेदी* कार्यकारी सम्पादक : एस.एन.लाल सम्पादकीय सलाहकार : मनोज तिवारी प्रबन्धक : एस.पी.द्विवेदी
सम्पर्क : 9450097512, 0522-4001081, 9307282052, e-mail: khushisamay.india@gmail.com , शाखा कार्यालय : 338, तृतीय तल, प्रिन्स काम्प्लेक्स, हज़रतगंज, लखनऊ, रामाज्ञा, गोईन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ